

मुकदमों का विवरण

नुतन कुमारी बनाम।

बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय और अन्य (2013 की सिविल अपील संख्या 6232-6236)
12 अक्टूबर, 2023

[हिमा कोहली और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ को विश्वविद्यालय के अंतर्गत चार अलग-अलग कॉलेजों में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों-पी. टी. आई. के नेतृत्व में अपीलों को स्वीकार करने और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पी. टी. आई. की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द करने में न्यायसंगत ठहराया गया था।

सेवा विधि -चयन समिति द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया-जिसे चुनौती दी गई- विश्वविद्यालय द्वारा अपने चार घटक कॉलेजों में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों-पी. टी. आई. की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करना-अपीलकर्ता और निजी उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन, उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाए गए-चयन समिति ने उसी दिन चार कॉलेजों में आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए साक्षात्कार के चार अलग-अलग सेट आयोजित किए-साक्षात्कार में उम्मीदवारों को सौंपे गए अंकों में अच्छा अंतर-निजी उत्तरदाताओं का चयन-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि चयन अनुचित और मनमाना होने के कारण निजी उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया-हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया- सही:

आयोजित किया गया: एक बार विज्ञापन जारी हो जाने और चयन मानदंड निर्धारित हो जाने के बाद, चयन समिति द्वारा मानदंडों में ढील देने की बहुत कम गुंजाइश है, विशेष रूप से तब तक जब तक कि यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि चयन समिति द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया मनमाना, तर्कहीन और अलग रखी जाने योग्य थी, इस बात से सहमत है-मानदंड x 700

699

/

[2023] 14 एस सी आर।

निर्णय चनिर्णय यनिर्णय ननिर्णय निर्णय सनिर्णय मनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय िनिर्णय निर्णय दनिर्णय णनिर्णय वनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय निर्णय ननिर्णय निर्णय तनिर्णय

[illegible]

[illegible]

सेवा न्यायशास्त्र-चयन प्रक्रिया-चयन समिति की शक्ति:

आयोजित किया गया:चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के नियमों और शर्तों से बंधी होती है-जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि कोई विज्ञापन किसी कानून या लागू नियमों के विपरीत जारी किया गया है, यह सभी प्रतिभागियों के लिए बाध्यकारी है-यहां तक कि चयन समिति के पास चयन के लिए एक अलग पैमाना या आधार निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह चयन के नियमों को लागू करने के समान होगा-एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों में बदलाव नहीं किया जा सकता है-एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद और चयन मानदंड निर्धारित हो जाने के बाद, चयन समिति द्वारा मानदंडों में ढील देने की बहुत कम गुंजाइश है, जब तक कि यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार था-यदि चयन होता है -[पैरा 10,10.4]

सेवा न्यायशास्त्र-नियुक्ति/चयन-चयन का निहित अधिकार:

आयोजित किया गया:केवल एक विज्ञापन के अनुसार एक पद के लिए आवेदन करने से, एक उम्मीदवार स्वचालित रूप से चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है-वह 701

केवल मौजूदा नियमों के अनुसार सख्ती से चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त करता है।[पैरा 10.3]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

डॉ. कृष्ण चंद्र साहू और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य

(1995) 6 एससीसी 1:[1995] 3 पूरक।एस. सी. आर. 419; संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 1910:[1968] 1 एससीआर 111; बी. एस. यादव और अन्य

v. हरियाणा राज्य और अन्य (1980) पूरक।एससीसी 524; पी. के. रामचंद्र अय्यर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 2 एस. सी. सी. 141:[1984] 2 एस. सी. आर. 200; उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1985) 3 एस. सी. सी. 721: [1985] 2 पूरक।एस. सी. आर. 367; दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य

(1987) 4 एससीसी 646:[1987] 3 एस. सी. आर. 1097; बेदंगा तालुका बनाम सैफुदाउल्ला खान और अन्य (2011) 12 एस. सी. सी. 85:[2011] 11 एस. सी. आर. 635; कृष्ण राय और

अन्य बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य (2022) 8 एस. सी. सी. 713:[2022] 8 एससीसी 713; एन. टी. देवीन कट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य (1990) 3 एस. सी. सी. 157; सुरेश कुमार ललितकुमार पटेल बनाम गुजरात राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 167; सचिव, ए. पी. लोक सेवा आयोग और बी. स्वप्ना और अन्य (2005) 4 एससीसी 154:[2005] 2 एससीआर

991; महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य (1990) 1 एससीसी 411:[1989] 2 पूरक।

एससीआर 385; गोपाल कृष्ण रथ बनाम एम. ए. ए. बेग (1999) 1 एससीसी 544: [1999] 1 एस. सी. सी. 544; रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ (1984) 2 एस. सी. सी. 141:[1984]

2 एस. सी. आर. 200-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील अतिरिक्त 2013 की सिविल अपील Nos.6232-6236।

2011 के एल. पी. ए. Nos.408,482,593,713 और 751 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

टी. वी. जॉर्ज, पंकज बिष्ट, विजय रावत, ड्रोन शर्मा, शाजी सेबेस्टियन, सनातन घोष, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

प्रेम सुंदर झा, आनंद के., सुश्री श्रुति गोपाल अय्यर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

नूतन कुमारी बनाम बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय 702 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

1. अपीलार्थी 1 पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 16 मई, 2011 को पारित निर्णय से व्यथित है, जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 के नेतृत्व में, जो प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय के अंतर्गत चार अलग-अलग कॉलेजों में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक 3 के रूप में काम कर रहे हैं, अपील 2 को अनुज्ञात गई थी और 10 फरवरी, 2011 के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को 2020 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 14,680 में पारित किया गया था, जिसके नेतृत्व में अपीलार्थी ने अपनी सेवाओं को समाप्त कर दिया था। यह और स्पष्ट किया गया कि यदि कुलाधिपति सहित प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय इतना इच्छुक है, तो वे निजी प्रत्यर्थियों को उचित सूचना देने के बाद मामले में निर्देशित जांच के साथ नए सिरे से आगे बढ़ने के हकदार होंगे।

2. हम पहले मामले के कुछ प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं।

2.1.प्रत्यर्थी द्वारा 13 जुलाई, 2008 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें इसके चार घटक कॉलेजों में पी. टी. आई. की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन में तीन विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:-

(क) प्रत्येक उम्मीदवार प्रत्येक कॉलेज के संबंध में पी. टी. आई. के पद के लिए अलग से आवेदन करेगा।

(बी) विषय पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ शारीरिक शिक्षा या स्नातक में स्नातक की डिग्री का होना था।

(ग) सभी पदों के लिए आयु सीमा सरकारी नियमों/आदेशों के अनुसार निर्धारित की गई थी।

2.2.उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार, अपीलार्थी और निजी उत्तरदाताओं ने कई अन्य लोगों के साथ अपने आवेदन जमा किए

1 पार्टियों का वर्णन उस तरीके से किया गया है जिसमें उन्हें सिविल अपील संख्या 6232/2013 में रखा गया है।

2 लेटर पेटेंट अपील सं. 408/2011, 482/2011, 593/2011, 713/2011 और 751/2011 3 संक्षेप में 'पी. टी. आई.' 703

नूतन कुमारी बनाम बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय 704

आवेदक। सभी पक्षों ने चार कॉलेजों में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए।

2.3.यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी और निजी उत्तरदाता संख्या 5 से 8 को योग्य पाया गया और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार आयोजित करने के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने एक सदस्य चयन समिति का गठन किया।

2.4.चयन समिति की बैठक 6 नवंबर, 2008 को हुई और उसने आवेदकों का साक्षात्कार लिया। समिति ने प्रश्न चार कॉलेजों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए साक्षात्कार के चार अलग-अलग सेट आयोजित किए। इसके बाद एक योग्यता सूची तैयार की गई। उक्त योग्यता सूची के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि वर्तमान कार्यवाही में सभी पक्षों का चयन समिति द्वारा चार कॉलेजों में उपलब्ध पदों के लिए एक ही दिन साक्षात्कार किया गया था, लेकिन चार अलग-अलग समय पर, साक्षात्कार के दौरान अपीलार्थी और उत्तरदाता संख्या 5 से 8 को दिए गए अंकों में बहुत अंतर था। इस पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से ध्यान दिया, जिन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“इस स्तर पर, मैं एक बात देख सकता हूं जो योग्यता सूची के सारणीकरण में अलग है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी चार कॉलेजों के लिए सभी एफ. आई. वी. रिट

याचिकाकर्ताओं का साक्षात्कार एक ही व्यक्ति की एक ही समिति द्वारा कथित रूप से एक ही दिन में चार बार किया गया था। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अन्य सभी अंक और उच्च योग्यता के लिए अंक और अनुभव सभी चार चार्टों में समान थे, लेकिन साक्षात्कार (वाइवा) में दिए गए अंक काफी भिन्न थे। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता, नूतन कुमारी को एक साक्षात्कार में 30 में से 24 अंक दिए गए थे और 30 में से 16 को 30 में से तीसरे 12 में और चौथे में 30 में से 20 में। इस तरह की अनियमित भिन्नता सभी चार योग्यता सूचियों में होती है जहां कोई एक में कम और दूसरी में अधिक अंक प्राप्त करता है। विश्वविद्यालय इन चिह्नों के लिए कोई औचित्य देने में सक्षम नहीं है। अन्य चिह्नों के विवरण पर उचित स्तर पर चर्चा की जाएगी। 14 फरवरी, 2009 को परिणामों को सारणीबद्ध करने पर विश्वविद्यालय ने नूतन कुमारी को छोड़कर चार रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किए। जाहिरा तौर पर, चार चयनित याचिकाकर्ताओं ने फरवरी में तुरंत अपनी नियुक्ति दे दी।

4 27 अक्टूबर, 2008 के आधिकारिक आदेश के माध्यम से

/

[2023] 14 एस सी आर।

2009 स्वयं। इसके बाद, कुलपति के आदेश के अनुसार, आधिकारिक आदेश दिनांक 13.05.2009 द्वारा, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने उनके वेतनमान को Rs.5000-150-8000 पर निर्धारित किया। "

2.5. जैसा कि उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है, अपीलार्थी का उसी दिन एक ही चयन समिति द्वारा चार बार साक्षात्कार किया गया था और प्रत्येक बार, उसे सौंपे गए अंक 12 से 16 से 20 से 24 (कुल 30 अंकों में से) थे।

2.6. फरवरी, 2009 में, चार चयनित उम्मीदवारों, यानी उत्तरदाता संख्या 5 से 8 ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी और प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, उनके वेतनमान को 13 मई, 2009 के आदेश द्वारा निर्धारित किया गया था।

2.7. अभिलेख से यह पता चलता है कि इसके तुरंत बाद, बिहार विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को उपरोक्त चयन प्रक्रिया के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं और 18 जून, 2009 के आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा पी. टी. आई. के संबंध में अपनाई गई चयन प्रक्रिया की जांच के लिए तीन सदस्यों की समिति (जांच समिति) नियुक्त की गई थी।

2.8. इसमें अपीलार्थी ने कुलाधिपति के समक्ष चयन समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित करने के तरीके के बारे में भी विरोध दर्ज कराया। जांच समिति ने 7 अक्टूबर, 2009 को प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें की गई नियुक्तियों को रद्द करने और विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कुलाधिपति ने पी. टी. आई. के पद पर

की गई नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश दिया और प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय को 5 जनवरी, 2010 के संचार के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

2.9. परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने 15 फरवरी, 2010 को उत्तरदाता संख्या 5 से 8 को एक अलग पत्र जारी किया, जिन्हें विषय पद के लिए चुना गया था, जिसमें उनसे कारण दिखाने के लिए कहा गया था कि उनकी नियुक्तियों को क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उक्त नोटिस को प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग रिट याचिकाओं का नेतृत्व किया।

5 2010 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3580, 2010 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3611, 2010 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3713 और 2010 705 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3724

नूतन कुमारी बनाम बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय 706

न्यायालय जिसका निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 10 फरवरी, 2011 के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया गया था।

3. विशेष रूप से, उत्तरदाता संख्या 5 से 8 को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए जाने से पहले, अपीलार्थी ने एक अलग रिट याचिका 6 का नेतृत्व किया जिसमें उत्तरदाता संख्या 5 से 8 के चयन को चुनौती दी गई थी। इसके बाद, अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नेतृत्व में सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया गया और 10 फरवरी, 2011 के सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया। अपीलार्थी के नेतृत्व में रिट याचिका को अनुज्ञात गई और उत्तरदाता संख्या 5 से 8 के नेतृत्व में उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

4. उपरोक्त निर्णय से व्यथित, उत्तरदाता संख्या 5 से 8 ने डिवीजन बेंच के समक्ष इंटर न्यायालय अपील 7 को प्राथमिकता दी। आक्षेपित निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सुविचारित आदेश को दरकिनार कर दिया है और कहा है कि केवल इसलिए कि चयन समिति द्वारा आयोजित चार अलग-अलग साक्षात्कारों में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में कुछ भिन्नताएं थीं, यह निश्चित रूप से संकेत नहीं देगा कि हस्तक्षेप की आवश्यकता के कारण चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित थी। डिवीजन बेंच ने उक्त मुद्दे पर गौर करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को फटकार लगाई और कहा कि सभी उम्मीदवारों को एक ही मानदंड के अधीन किया गया था और इसलिए, किसी भी भेदभाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। नतीजतन, अपीलार्थी के नेतृत्व में रिट याचिका 4 एफ. आई., जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञात गई थी, को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया गया।

5. जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 (खंड पीठ के समक्ष अपीलकर्ताओं) का संबंध है, यह देखा गया कि चूंकि कुलाधिपति, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा आदेशित जांच के चरण में

उक्त प्रत्यर्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए उनकी समाप्ति विधि ी रूप से खराब थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी। परिणामस्वरूप, कुलाधिपति द्वारा जारी निर्देशों सहित निजी उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया गया और प्रत्यर्थियों को उचित सूचना देने के बाद अधिकारियों को नए सिरे से जांच के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई।

6 2009 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 14,680

7 पत्र पेटेंट अपील सं. 482/2011, 408/2011, 593/2011, 713/2011 और 751/2011

/

[2023] 14 एस सी आर।

6. यह उपरोक्त निर्णय है जिसने अपीलार्थी को इस न्यायालय के समक्ष लाया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि डिवीजन बेंच के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक सुविचारित और विश्लेषण किए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं था, जिसमें निर्णय वापस करने से पहले सभी पहलुओं पर गुण-दोष के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड पीठ ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि साक्षात्कार में अपीलार्थी को सौंपे गए अंकों में भारी भिन्नताएं थीं जिन्हें "कुछ भिन्नता" के रूप में नहीं कहा जा सकता है जैसा कि आक्षेपित निर्णय में वर्णित किया जाना चाहिए। जबकि एक साक्षात्कार में, अपीलार्थी ने 30 में से 24 अंक प्राप्त किए थे, उसी दिन, उसी चयन समिति ने अपीलार्थी का एक और साक्षात्कार आयोजित करने पर उसे 30 में से 12 अंक दिए, इस प्रकार चयन प्रक्रिया के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया।

7. इसके बाद अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 6, श्री चंद्रमा सिंह, जिन्हें एक महिला कॉलेज (M.S.K.B कॉलेज, मुज़फ़्फ़रपुर) में पी. टी. आई. के रूप में चुना और नियुक्त किया गया था, अधिक उम्र के थे और इसलिए, विषय पद के लिए आवेदन करने के लिए भी अयोग्य थे। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 6 का जन्म 3 अप्रैल, 1971 को हुआ था; प्रश्न विज्ञापन 13 जुलाई, 2008 को प्रकाशित किया गया था और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त, 2008 थी। 13 अप्रैल, 2007 तक, प्रत्यर्थी संख्या 6 ने पहले ही 37 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी और इसलिए, विज्ञापन की तारीख पर ही वह स्पष्ट रूप से उम्र से अधिक था, यानी 13 जुलाई, 2008 को। इस पहलू को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विधिवत नोट किया गया था और अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुति को बरकरार रखा गया था, लेकिन खंड पीठ ने आक्षेपित निर्णय में उक्त मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। 8. उपरोक्त पहलू पर, प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदिश सी. अग्रवाल अपील पत्र पुस्तिका के साथ अपीलार्थी के नेतृत्व में एक दस्तावेज पर भरोसा करना चाहते हैं और जिसे "अनुलग्नक-पी4" के रूप में

चिह्नित किया गया है, जो प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय की अंतिम टिप्पणियों की एक टाइप की गई प्रति है, जिसमें कुलसचिव द्वारा यह दर्ज किया गया है कि उम्मीदवारों की आयु के संबंध में पात्रता की गणना करने के उद्देश्यों के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि आयु की गणना 1 जनवरी, 2008 को की जाएगी क्योंकि उक्त वर्ष में विज्ञापन प्रक्रिया शुरू की गई थी। कुलसचिव द्वारा की गई उक्त सिफारिश को उसी दिन कुलपति द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी।

707

नुतन कुमारी बनाम बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय 708

9. हमने अभिलेख का अध्ययन किया है और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

10. न्यायिक फैसलों में बार-बार यह माना गया है कि चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के नियमों और शर्तों से बाध्य है। जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि कोई विज्ञापन किसी क़ानून या लागू नियमों के विपरीत जारी किया गया है, तब तक यह सभी प्रतिभागियों के लिए इस हद तक बाध्यकारी है कि चयन समिति को भी चयन के लिए एक अलग मानदंड या आधार निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह चयन के विधायी नियमों के समान होगा। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को बदला नहीं जा सकता है। इसके पीछे एक ठोस तर्क है कि यदि चयन मानदंड के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उदाहरण के लिए मानकों को कम करके, तो एक पक्ष को एक वैध शिकायत हो सकती है कि अगर उसे पता होता कि मानदंड को बाद में कम किया जाएगा, तो वह भी उक्त पद के लिए आवेदन कर सकता था।

10.1. उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, हम उपयोगी रूप से निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

डॉ. कृष्ण चंद्र साहू और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य 8

जहाँ यह इस प्रकार आयोजित किया गया है: “31. अब, सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल के पास उपलब्ध है और इस शक्ति का उपयोग करते हुए ही वर्तमान नियम बनाए गए थे। यदि किसी मामले में संसद या राज्य विधानमंडल या उस मामले में राज्य के राज्यपाल द्वारा वैधानिक नियम नहीं बनाए गए हैं, तो उपयुक्त सरकार (अनुच्छेद 73 के अंतर्गत केंद्र सरकार और अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य सरकार) कार्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। हालाँकि, यदि नियम बनाए गए हैं, लेकिन वे किसी भी विषय या मुद्दे पर चुप हैं, तो चूक की आपूर्ति की जा सकती है और नियमों को कार्यकारी निर्देशों द्वारा पूरक किया जा सकता है (देखें -संत राम

शर्मा बनाम राजस्थान राज्य [ए. आई. आर **1967** एस. सी. **1910:(1968) 1** एससीआर **111:(1968) 2** एलएलजे **830**।]

8 (1995) 6 एससीसी 1

/

[2023] 14 एस सी आर।

32. तत्काल मामले में, सरकार ने न तो कोई प्रशासनिक निर्देश जारी किया और न ही उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के मानदंडों के संबंध में चूक की। चयन बोर्ड के सदस्यों ने, अपनी खुद की, उन उम्मीदवारों की विश्वसनीय चरित्र सूची को अपनाने का फैसला किया, जो पहले से ही होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आधार के रूप में।

33. चयन बोर्ड के सदस्यों या उस मामले के लिए, किसी अन्य चयन समिति के पास चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि वे अनुच्छेद **309** के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा उस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत नहीं हैं।

[जोर दिया गया]

(यह भी देखें -बी. एस यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **9**; पी. के. रामचंद्र अय्यर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **10**; उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य **11**; और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य **12**)

10.2. बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदाउल्ला खान और अन्य **13** में, यह

न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि निर्धारित चयन प्रक्रिया में ढील देने की किसी भी शक्ति का विज्ञापन में निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया जाना चाहिए:-

“29. हमने पूरे मामले पर विस्तार से विचार किया है। हमारी राय में, यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी और दोहराव की आवश्यकता है कि सार्वजनिक कार्यालयों में सभी नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी उम्मीदवार को किसी भी अनुचित पक्ष के परिणामस्वरूप कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए।

इसलिए, चयन प्रक्रिया निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से आयोजित की जानी चाहिए। नतीजतन, जब किसी विज्ञापन में किसी विशेष अनुसूची का उल्लेख किया जाता है, तो उसे सावधानीपूर्वक बनाए रखना पड़ता है। विज्ञापन के नियमों और शर्तों में कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

9 (1980) सप.एससीसी 524 10 (1984) 2 एससीसी 141 11 (1985) 3 एससीसी 721 12 (1987) 4 एससीसी 646 13 (2011) 12 एससीसी 85 709

नूतन कुमारी बनाम बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय 710

जब तक कि ऐसी शक्ति विशिष्ट रूप से आरक्षित न हो। इस तरह की शक्ति प्रासंगिक वैधानिक नियमों में सुरक्षित रखी जा सकती है। भले ही नियमों में छूट की शक्ति प्रदान की गई हो, फिर भी विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। नियमों में ऐसी शक्ति के अभाव में, इसे अभी भी विज्ञापन में प्रदान किया जा सकता है। हालाँकि, यदि विश्राम की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसे उचित प्रचार दिया जाना चाहिए। यह होगा

यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जो उम्मीदवार छूट के कारण पात्र हो जाते हैं, उन्हें आवेदन करने का समान अवसर दिया जाए और

प्रतिस्पर्धा करें। उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन में किसी भी शर्त में ढील देना भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** और **16** में निहित समानता के जनादेश के विपरीत होगा।

30. इस मामले में विज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि छूट की कोई शक्ति नहीं थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देने में त्रुटि की कि प्रत्यर्थी 1 के मामले में आवेदन पत्र के साथ या प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने से पहले विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में शर्त में ढील दी जा सकती है। इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं होगी क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश का उल्लंघन करेगा। "

[जोर दिया गया]

(यह भी देखें - कृष्ण राय और अन्य बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य 14)

10.3. यह स्थापित सेवा न्यायशास्त्र का भी एक हिस्सा है कि केवल एक विज्ञापन के अनुसार एक पद के लिए आवेदन करने से, एक उम्मीदवार स्वचालित रूप से चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है। वह केवल मौजूदा नियमों के अनुसार सख्ती से चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त करता है।

इस न्यायालय ने एन. टी. देवीन कट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य 15 मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“11. प्रश्न का एक और पहलू भी है। जहां पदों की एक श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन मौजूदा नियमों या सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा,

14 (2022) 8 एससीसी 713 15 (1990) 3 एससीसी 157

और यदि यह आगे विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण की सीमा को इंगित करता है, तो ऐसे मामले में उम्मीदवारों का चयन तत्कालीन मौजूदा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं, और लिखित या मौखिक परीक्षा से गुजरते हैं, वे विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने का निहित अधिकार प्राप्त करते हैं, जब तक कि विज्ञापन स्वयं एक विपरीत इरादे का संकेत नहीं देता है। आम तौर पर, ए

उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किए जाने का अधिकार है क्योंकि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को उसका अधिकार स्पष्ट हो जाता है, हालांकि उसके पास नहीं है

मामले में पूर्ण अधिकार। यदि चयन के लंबित रहने के दौरान भर्ती नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन किया जाता है, तो उस स्थिति में चयन संशोधित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमों में पूर्वव्यापी प्रभाव है या नहीं, यह मुख्य रूप से नियमों की भाषा और विधायी इरादे का पता लगाने के लिए इसके निर्माण पर निर्भर करता है। विधायी आशय का निर्धारण या तो स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किया जाता है; यदि संशोधित नियम प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं हैं तो चयन को उन नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए जो विज्ञापन की तारीख को लागू थे। इस प्रश्न का निर्धारण काफी हद तक विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और

संबंधित नियम और आदेश। ऐसा न हो कि कोई भ्रम हो, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक विज्ञापन के अनुसरण में किसी पद के लिए आवेदन करने पर एक उम्मीदवार चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है, लेकिन यदि वह पात्र है और अन्यथा प्रासंगिक नियमों और विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार योग्य है, तो वह चयन के लिए विचार किए जाने का एक निहित अधिकार प्राप्त करता है जो नियमों के अनुसार है क्योंकि वे नियमों पर मौजूद थे।

विज्ञापन की तिथि। उन्हें चयन के लंबित रहने के दौरान नियमों के संशोधन पर उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि संशोधित नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के न हों। "

[जोर दिया गया]

(यह भी देखें -सुरेश कुमार ललितकुमार पटेल बनाम गुजरात राज्य 16)

10.4. इसके अलावा, एक बार विज्ञापन जारी होने और चयन मानदंड निर्धारित होने के बाद, चयन समिति द्वारा मानदंडों में ढील देने की बहुत कम गुंजाइश है, विशेष रूप से, जब तक कि यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी। हम इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

सचिव, ए. पी. लोक सेवा आयोग और बी. स्वप्ना और अन्य **17**

जो निम्नलिखित शब्दों में नियमों के अंतर्गत निर्धारित चयन के मानदंडों में हस्तक्षेप करने के प्रतिकूल परिणामों पर प्रकाश डालता है:

“14. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि संशोधित नियम लागू था। जैसा कि प्रतिवादी 1 आवेदक के विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि यह अपरिवर्तित नियम था जो लागू था। एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, निर्धारित चयन मानदंडों को बदला नहीं जा सकता है। इसके पीछे का तर्क निष्पक्ष खेल पर आधारित है। एक व्यक्ति जिसने एक निश्चित मानदंड जैसे न्यूनतम प्रतिशत अंकों के कारण आवेदन नहीं किया है, वह एक वैध शिकायत कर सकता है, यदि उसे कम किया जाता है, तो वह आवेदन कर सकता था क्योंकि उसके पास उक्त प्रतिशत था। चयन प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान यदि संशोधन किया जाता है तो नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारण के संबंध में नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक कानून या वैधानिक नियम संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी प्रभाव के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं किया जाता है। जब तक कि कानून या नियमों में ऐसे शब्द नहीं हैं जो मौजूदा अधिकारों को लागू करने के इरादे को दर्शाते हैं, तब तक नियम को संभावित माना जाना चाहिए। यदि नियम को ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो किसी भी व्याख्या में काफी सक्षम है तो इसे संभावित माना जाना चाहिए।

केवल। (पी. महेन्द्रन बनाम कर्नाटक राज्य देखें **[(1990) 1 एस. सी. सी. 411:1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 163:(1990) 12 एटीसी 727]** और गोपाल कृष्ण रथ बनाम एम. ए. ए. बेग **[(1999) 1 एससीसी 544:1999 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 325]**।)

15. एक अन्य पहलू जिस पर इस न्यायालय ने प्रकाश डाला है, वह है मानदंडों में ढील देने की गुंजाइश। यद्यपि न्यायालय को संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा कर्तव्यों के निष्पादन पर सम्मान के साथ विचार करना चाहिए, लेकिन वह नियम पर आधारित समाज की शुरुआत करने के अपने कार्यों का त्याग नहीं कर सकता है।

विधि से। एक बार जब यह सबसे संतोषजनक रूप से स्थापित हो जाता है कि चयन समिति के पास आवश्यक योग्यता में ढील देने की शक्ति नहीं थी, तो चयन की पूरी प्रक्रिया जहां तक चयनित उम्मीदवार की बात है,

नूतन कुमारी बनाम बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय 712 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

चिंतित हो जाता है। पी. के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ [(1984) 2 एस. सी. सी. 141:1984 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 214] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि आवश्यक योग्यता में ढील देने की कोई शक्ति नहीं है, उम्मीदवार के चयन की पूरी प्रक्रिया विज्ञापन द्वारा निर्धारित स्थापित मानदंडों का उल्लंघन थी। आराम करने की शक्ति को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और अन्यथा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। "

[जोर दिया गया]

11. हाथ में मामले पर वापस आते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं में अभिलेख और अभिवचनों की सावधानीपूर्वक जांच की है और प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं:

“शारीरिक शिक्षा योग्यता तीन प्रकार की होती है। पहला इंटरमीडिएट के बाद तीन साल का शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम है जिसके परिणामस्वरूप बी. पी. ई. की डिग्री होती है। दूसरा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट और एक साल के शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के बाद किसी भी विषय में तीन साल का स्नातक पाठ्यक्रम है जो बी. पी. एड. तक जाता है। डिग्री और तीसरा इंटरमीडिएट के बाद किसी भी विषय में तीन साल का स्नातक पाठ्यक्रम और स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित एक साल का शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जो डी. पी. एड के लिए अग्रणी है। साक्षात्कार की तिथि पर चयन समिति ने स्नातक स्तर के लिए अंकन प्रणाली विकसित की जो ऊपर उल्लिखित इस प्रकार थी।

बी. पी. ई. और बी. पी. एड. वाले उम्मीदवारों के लिए बी. पी. ई. और बी. पी. एड. में प्राप्त उनके अंक केवल श्रेणीबद्ध तरीके से लिए गए थे। यदि उन्होंने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें 40 में से 40 दिए जाते हैं, यदि उन्होंने 60-75% प्राप्त किया है तो उन्हें 40 में से 30 दिए जाते हैं, यदि उन्होंने 45-60% प्राप्त किया है तो उन्हें 40 में से 25 दिए जाते हैं और यदि उन्होंने 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें 40 में से 20 दिए जाते हैं लेकिन जब डी. पी. एड. की बात आती है तो उनके प्राप्त अंकों की गणना अलग-अलग तरीके से की जाती है। स्नातक के लिए 40 में से उनके अंकों को 20 अंकों में से दो में विभाजित किया गया था, उनके तीन साल के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 20 अंक और उनके शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए केवल 20 अंक अधिकतम थे। परिणाम यह हुआ कि याचिकाकर्ता नूतन कुमारी के पास डी. पी. एड. में 83.6% था, लेकिन उन्हें केवल 20 अंक दिए गए, जबकि अन्य जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे लेकिन 713।

बी. पी. ई. या बी. पी. एड. रखने वालों को उनके स्नातक या अन्य अंकों को नजरअंदाज करते हुए उस आधार पर उच्च अंक दिए जाते थे। उदाहरण के लिए, 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले रविशंकर कुमार को 40 अंक दिए गए, आईडी। प्राप्त करने वाले मिथिलेश कुमार मणि को 30 अंक दिए गए, 55 प्रतिशत प्राप्त करने वाले चंद्रमा सिंह को 25 अंक दिए गए और 57 प्रतिशत प्राप्त करने वाले संजय कुमार सिंह को 25 अंक दिए गए।

फिर चुनौती उच्च योग्यता और अनुभव पर अंकों की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों अलग-अलग मानदंड हैं लेकिन कुल अंकों को संयुक्त रूप से 10 पर निर्धारित किया गया है जो किसी भी विभाजन या किसी भी मानदंड का खुलासा नहीं करता है।

फिर वाइवा (साक्षात्कार) के लिए अंक हैं, जो कुल अंकों का 30 प्रतिशत है, जैसा कि शुरुआत में ही उल्लेख किया गया है, उसी दिन पांच सदस्यों के एक ही समूह ने चयनित उम्मीदवारों का चार बार साक्षात्कार किया, प्रत्येक कॉलेज के लिए एक बार और काफी अलग-अलग अंक दिए। सबसे पहले, इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह व्यक्तिपरक संतुष्टि पर अनियमित तर्कहीन अंकन को दर्शाता है, जो साक्षात्कार अंक 30 प्रतिशत तक अधिक होना तर्कहीन है, विशेष रूप से जब यह दिखाया जाता है कि चयन और गैर-चयन के बीच अंतर मुश्किल से कुछ ही अंक था। "

12. पूरे अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं:-

“प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मेरे विचार में, शत्रुतापूर्ण भेदभाव और मनमानेपन अभिलेख के सामने बड़े पैमाने पर लिखा गया है। किसी भी उचित निश्चितता के साथ कोई भी चयन प्रक्रिया या प्रक्रिया को नहीं जानता था। यह निर्विवाद है कि मानदंड केवल साक्षात्कार की तारीख को निर्धारित किए गए थे, तब भी लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से खराब और गलत प्रशासनिक कार्रवाई का मामला है। बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है और इस तरह की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा पवित्र नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह कहना कि याचिकाकर्ता नूतन कुमारी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और नियुक्तियों के बाद इसे चुनौती नहीं दे सकती थीं, न्याय का उपहास होगा। कोई भी चुनौती दे सकता था

मानदंड यदि विज्ञापन में या साक्षात्कार से पहले या चयन से पहले उनका खुलासा किया गया था, लेकिन यह सब गुप्त रखा गया था। यह बहुत बाद में नियुक्तियों के बाद पता चला। यह नूतन कुमारी को उस चीज़ को चुनौती देने से नहीं रोक सकता जिसे वह नहीं जानती थी और क्या

कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। विश्वविद्यालय और अन्य याचिकाकर्ताओं की इस आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है। मेरे विचार में, विधि तय हो गया है। यदि ए.

व्यक्ति चयन प्रक्रिया को जानते हुए अपनी आंखें खुली रखते हुए चयन प्रक्रिया में भाग लेता है, फिर चयन में विफल होने पर वह मुड़कर उसे चुनौती नहीं दे सकता है। उसे उसी के लिए सहमति माना जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाँच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट देने से पहले ही नूतन कुमारी ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी। चुनौती को मामले के किसी भी पहलू में विलंबित नहीं कहा जा सकता है। मानदंड का खुलासा नहीं किया गया था। यह केवल कुछ हद तक मानदंड का खुलासा होने के बाद ही कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति चुनौती देने की स्थिति में था।

यदि इसे ध्यान में रखा जाए तो यह देखा जाएगा कि चुनौती में कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी। इसके अलावा, चयन प्रक्रिया में मनमानेपन की सीमा, जैसा कि देखा जाएगा, चयन प्रक्रिया और स्वयं चयन अपास्त करते हुए रखने में पूरी तरह से उचित है।

अब, स्नातक के संबंध में चिह्नों पर आते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम तीन प्रकार के होते हैं। एक इंटरमीडिएट के बाद तीन साल का पाठ्यक्रम है और अन्य दो किसी भी विषय में तीन साल के स्नातक के बाद एक साल के पाठ्यक्रम हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है या एक साल का डिग्री पाठ्यक्रम क्योंकि कानून के अंतर्गत अकेले विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान कर सकता है, स्कूल परीक्षा बोर्ड नहीं कर सकता है और यही इसका एकमात्र कारण है।

भेद करना। यदि वर्गीकरण किया जाना था, बशर्ते कि यह उचित हो, तो यह तीन साल के शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम और एक साल के शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के बीच हो सकता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विज्ञापन में सभी को बिना किसी वरीयता के पात्रता के लिए समान रूप से माना जाता है। या भेद। यदि विज्ञापन में स्वयं कोई अंतर या अलग उपचार नहीं दिया गया है तो मूल्यांकन के समय कोई नया मानदंड नहीं है।

स्थापित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता नूतन कुमारी के अंक पत्र से प्रभाव स्पष्ट है। उन्होंने D.P.Ed में 83.6% अंक प्राप्त किए और तीन साल के स्नातक पाठ्यक्रम में उन्हें 48.8% प्राप्त हुआ। इस प्रकार, कुल मिलाकर उन्हें 40 अंकों में से क्रमशः 20 और 12 के 32 अंक दिए गए। रविशंकर कुमार के पास या तो बी. पी. ई. या B.P.Ed में 80 प्रतिशत था। उन्हें 40 दिया गया था।

40 में से अंक। विभिन्न उदाहरण हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मनमाने मानदंड के मनमाने परिणामों को दिखाने के लिए, जो मानदंड हैं, 715

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, साक्षात्कार के समय तय किया गया था। जब सभी आवेदनों की जांच की गई थी, तो यह दावा कि ये मानदंड कुछ उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए थे, इसलिए इसे निराधार नहीं कहा जा सकता है।

एक बार फिर, जब हम उच्च योग्यता और अनुभव के अंकों की बात करते हैं, तो किसी ने यह खुलासा नहीं किया है कि इस शीर्ष के अंतर्गत अंक देने का मानदंड क्या था। एक बार फिर, यह चयन समिति की सनक पर छोड़ दिया जाता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर से, हम साक्षात्कार के लिए अंकों के मामले में आते हैं, चीजें सबसे खराब हैं। एक ही दिन पांचों लोगों के एक ही समूह ने सभी पांचों याचिकाकर्ताओं का चार बार साक्षात्कार लिया। एक ही नौकरी के लिए और प्रत्येक साक्षात्कार में

निशान बहुत भिन्न होते हैं। ये व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर व्यक्तिपरक मूल्यांकन हैं-ये वे अंक हैं जिन्होंने पर्याप्त अंतर बनाया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मार्जिन बहुत कम है। इसके अलावा, इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि व्यक्तिपरक अंक, नियुक्ति की प्रकृति में, 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर प्रक्रिया को काफी मनमाना और भेदभावपूर्ण बनाती हैं। इस प्रकार, समग्र रूप से अपनाई गई प्रक्रिया को विधि में वैध नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रक्रिया को बंद कर दिया जाना चाहिए और बंद कर दिया जाना चाहिए। नतीजतन, यह माना जाता है कि चयन खराब था। "

[जोर दिया गया]

13. जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने चयन समिति द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया की जांच करने के लिए कड़ी मेहनत की और यह निर्णय दिया कि यह मनमाना, तर्कहीन और अलग किए जाने योग्य है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वापस किए गए उक्त आदेशों से सहमत हैं।

14. चयन प्रक्रिया के लिए अपीलार्थी द्वारा दी गई चुनौती को ध्यान में रखते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से जो सामने आता है वह इस प्रकार है:-

(i) कि चयन समिति साक्षात्कार आयोजित करने की तारीख को उम्मीदवारों को अंक निर्धारित करने के मानदंडों को तय करने के लिए आगे बढ़ी। उक्त मानदंड न तो विज्ञापन में प्रकट किए गए थे, न ही साक्षात्कार आयोजित करने से पहले या यहां तक कि उम्मीदवारों को बताए गए थे।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(ii) यद्यपि विज्ञापन में केवल आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, चयन समिति ने अपने दम पर कुल 100 अंक निर्धारित किए हैं और विभिन्न शैक्षणिक योग्यता के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किए हैं, अर्थात् मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटरमीडिएट के लिए 10 अंक और स्नातक के लिए 40 अंक।

(iii) साक्षात्कार के लिए अंक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दिन ही कुल अंकों के 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किए गए थे। विशेष रूप से प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करने के बजाय, क्योंकि उन सभी ने प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय के अंतर्गत चार घटक कॉलेजों में नियुक्ति के लिए अलग-अलग आवेदन किए थे और जमा किए थे, समिति ने विभिन्न कॉलेजों में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से प्रत्येक के संबंध में साक्षात्कार के चार सेट आयोजित करने का निर्णय लिया। साक्षात्कार में दिए गए अंकों पर बारीकी से नज़र डालने से चयन समिति के सदस्यों द्वारा किए गए अनियमित मूल्यांकन को दिखाया गया।

15. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला कि चयन समिति द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया दूषित थी और न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकती थी।

16. जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 6 का संबंध है, ऊअंतर्गत की गई टिप्पणियों के अलावा, हम यह भी नोट न्यायालय सकते हैं कि सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विषय पद अंतर्गत नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष थी और अनारक्षित श्रेणी (महिला) के लिए 40 वर्ष थी। प्रत्यर्थी सं. 3, कुलसचिव, बिहार विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जवाबी हलफनामे में पैराग्राफ 14 में इस प्रकार कहा गया है:-

“आधार के पैराग्राफ 5 (सी) के जवाब में कहा गया है कि विज्ञापन में निहित के रूप में, पद के लिए आयु सीमा सरकारी नियम या आदेश के अनुसार लागू होगी। यह कहा गया है कि सरकार ने आयु निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त निर्धारित की है।”

17. प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए उपरोक्त स्पष्ट रुख के आलोक में कि 717 की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि

नुतन कुमारी बनाम बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय 718

लागू नियमों के संदर्भ में आवेदकों को प्रत्येक वर्ष के अगस्त के पहले दिन के रूप में लिया जाना था, जिसका वर्तमान मामले में अर्थ 1 अगस्त, 2008 होगा, स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी संख्या 6 को विषय पद के लिए आवेदन करने के लिए भी योग्य नहीं ठहराया गया था, जिसने सामान्य श्रेणी (पुरुष) उम्मीदवार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु, यानी 37 वर्ष को पार कर लिया था। किसी भी स्थिति में, विज्ञापन में उल्लिखित सरकारी नियम/आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जवाबी हलफनामे में विस्तृत किया गया है, उत्तरदाता संख्या 5 से 8 द्वारा

विश्वविद्यालय की आंतरिक सूचनाओं पर कोई भी निर्भरता रखने की मांग की गई है, वह भी विज्ञापन जारी करने की तारीख (25 अक्टूबर, 2008 से 27 अक्टूबर, 2008) के बहुत बाद, इसका कोई परिणाम नहीं होगा।

18. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के 10 फरवरी, 2011 के निर्णय को बहाल कर दिया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम के रूप में, उत्तरदाता संख्या 5,7 और 8 के संबंध में नियुक्ति आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 विषय पद पर आवेदन करने के लिए अयोग्य होने के कारण, उसके आवेदन को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था और इसलिए, उसके नियुक्ति आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। यह हमें प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय के अंतर्गत चार घटक कॉलेजों में पी. टी. आई. के चार पदों के साथ छोड़ देता है जिन्हें भरने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए, विश्वविद्यालय को एक चयन समिति गठित करने का निर्देश देना उचित समझा जाता है, जो अपीलार्थी और उत्तरदाता संख्या 5,7 और 8 की उम्मीदवारी पर विचार करेगी। चयन समिति उपरोक्त उम्मीदवारों के संबंध में एक ही साक्षात्कार आयोजित करेगी, चाहे वे विषय पदों के लिए कितने भी आवेदन कर चुके हों। साक्षात्कार आयोजित करते समय, उम्मीदवारों के पास मौजूद विभिन्न योग्यताओं के लिए कोई अलग अंक निर्धारित नहीं किए जाएंगे क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी।

19. चयन समिति द्वारा उपरोक्त उम्मीदवारों में से प्रत्येक की योग्यता के साथ-साथ आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में उन्हें आवंटित अंकों को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद, एक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और उम्मीदवारों को उक्त सूची के अनुसार संबंधित कॉलेजों को सौंपा जाएगा। समिति के गठन की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर पूरी कवायद पूरी कर ली जाएगी और अंतर्गत िणाम अपीलार्थी और उत्तरदाता संख्या 5,7 और 8 को सूचित करते हुए घोषित किए जाएंगे।

/

[2023] 14 एस सी आर।

20. यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस मामले के पिछले इतिहास को देखते हुए जहां कुलाधिपति और प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय के कुलसचिव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे और कुलाधिपति द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उपरोक्त अधिकारियों को अभ्यारोपित किया गया है, हम इस आदेश की एक प्रति उनके समक्ष रखे जाने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर विधि के अनुसार एक चयन समिति का गठन करना कुलाधिपति के विवेक पर छोड़ देते हैं।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि इसमें अपीलार्थी और उत्तरदाता संख्या 5 से 8 के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था, इसलिए चयन प्रक्रिया केवल उक्त पक्षों तक सीमित रहेगी।

22. दीवानी अपीलों की अनुज्ञात जाती है और उपरोक्त शर्तों पर उनका निपटारा किया जाता है।लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन